मनमानी | जिले वासियों के विरोध बावजूद पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप से मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री निर्माण शुरू

विरोध दरकिनार कर मेडिकल कॉलेज का निर्माण जारी

नवभारत, कटनी। जिले वासियों द्वारा लंबे समय से किए जा रहे लगातार विरोध और आपत्तियों को दरकिनार करते हुए आखिरकार जिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। कछगवां क्षेत्र के पास चिह्नित 25 एकड़ की विशाल भूमि पर इस प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम अब गुपचुप तरीके से बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार और स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन के बीच बाकायदा अनुबंध हुआ था। हालांकि इस अनुबंध के सामने आने के बाद से ही इसे पूरी तरह से शासकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी विरोध भी हुआ है। जनता और विभिन्न सामाजिक संगठनों का स्पष्ट कहना है कि स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा को निजी हाथों में सौंपने के बजाय सरकार को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। निर्माण स्थल से सामने आई मौजूदा स्थिति के अनुसार वर्तमान में साइट को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। सूत्रों और वहां कार्यरत मजदूरों के अनुसार इस बाउंड्री वॉल के निर्माण का ठेका मोहम्मद तमीम खान को सौंपा गया है। परियोजना की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निर्माण स्थल पर कंक्रीट मिक्सिंग के लिए बैचिंग प्लांट लगाया गया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में लोहा, रेत समेत अन्य आवश्यक निर्माण सामग्री का स्टॉक भी जमा कर लिया गया है। निर्माण कार्य अनवरत चलता रहे, इसके लिए मजदूरों के रहने के लिए क्वार्टर भी तैयार कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि जिले के नागरिक और विभिन्न संगठन इस परियोजना को निजी हाथों में सौंपने का शुरू से ही कड़ा विरोध कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के भूमिपूजन के लिए सूबे के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का दो बार कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन जनता के भारी विरोध और आक्रोश को देखते हुए दोनों ही बार मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। राजनेता और प्रशासनिक अमला भले ही भूमिपूजन की औपचारिक घोषणा से बचता रहा, लेकिन अब बिना किसी शोर-शराबे और वीआईपी आयोजन के अचानक निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कटनी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का स्वागत करते हैं, लेकिन इसे पीपीपी मॉडल के बजाय पूरी तरह शासकीय मोड में बनाया जाना चाहिए, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग को भी सस्ती व बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। पीपीपी मोड के मेडीकल कॉलेज के निर्माण के विरोध के बावजूद प्रदेश सरकार उसे बनवा रही है, जिले वासियों के विरोध को दरकिनार कर दिया गया है।

पुलिस गश्त को प्रभावी बनाए, बदमाशों पर रखें नजर

डीआईजी ने किया कोतवाली थाने का निरीक्षण

नवभारत, कटनी। डीआईजी जबलपुर रेंज अतुल सिंह ने सोमवार को कोतवाली थाना कटनी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने थाना अभिलेखों, विभिन्न रजिस्टरों, लंबित प्रकरणों की फाइलों, अपराध नियंत्रण के लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने थाना परिसर की साफ-सफाई, अभिलेखों के संधारण, मालखाना व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया।

डीआईजी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि आमजन से प्राप्त शिकायतों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए और प्रत्येक प्रकरण में समयबद्ध, प्रभावी कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने क्षेत्र में पुलिस गश्त को और अधिक प्रभावी बनाने, चिन्हित अपराधियों पर निगरानी रखने, उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर की यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि थाना आने वाले नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराना पुलिस की प्राथमिकता है। आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने जिले की वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

एक नजर में

नगर निगम में महापौर करेंगी जनसुनवाई

नवभारत, कटनी। शहरवासियों की समस्याओं के तत्काल, पारदर्शी और प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से आयोजित की जा रही महापौर जनसुनवाई अब एक भरोसेमंद और प्रभावी व्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुकी है। यह पहल नागरिकों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित कर समाधान की प्रक्रिया को सरल और तेज बना रही है। मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक नगर निगम के मेयर इन काउंसिल सभागार में महापौर जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शहर के नागरिक अपनी समस्याओं और शिकायतों से संबंधित आवेदन लेकर सीधे महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात रख सकेंगे। महापौर ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों को सुगम, सहज और समयबद्ध समाधान उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई के माध्यम से न केवल समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाता है, बल्कि संबंधित विभागों को मौके पर ही निर्देश देकर उनके तत्काल निराकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जाती है। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन लगातार इस दिशा में प्रयासरत है कि शहरवासियों को शाखाओं के चक्कर न लगाने पड़े, एक ही स्थान पर समस्याओं का समाधान किया जा सके।

घर से नकदी, जेवर और राशन तक लेकर भागे चोर

सूने मकान का ताला तोड़कर दिया वारदात को अंजाम

नवभारत, ढीमरखेड़ा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चोरों के हौसले बुलंद हैं। ढीमरखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम पाली में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए नगदी, सोने-चांदी के जेवरात सहित घर के कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया।

शातिर चोर घर में रखा गेंहू-चावल और रसोई का कुकर तक बटोर ले गए। घटना के समय गृहस्वामी परिवार सहित बाहर गया हुआ था। पुलिस ने फरियादिया की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ढीमरखेड़ा के ग्राम पाली निवासी ललिता मेहरा पति रमालाल मेहरा (35 वर्ष) का परिवार जब अपने घर में मौजूद नहीं था, तभी अज्ञात चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। चोरों ने कमरों और अलमारी के ताले चटकाकर अंदर रखी 65 हजार रुपए नगद राशि और सोने-चांदी के कीमती जेवरातों को पार कर दिया। हैरानी की बात यह है कि चोरों ने सिर्फ नगदी और जेवर ही नहीं समेटे, बल्कि घर के किचन और कोठी में रखा चावल, गेंहू और प्रेशर कुकर भी अपने साथ ले गए। वारदात के बाद जब पीड़ित परिवार वापस लौटा, तो घर का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए। अंदर का नजारा देखकर तत्काल ढीमरखेड़ा पुलिस को सूचना दी गई। ढीमरखेड़ा पुलिस ने फरियादिया ललिता मेहरा की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में विवेचना शुरू कर दी है।

क्षेत्र में पुराने बदमाशों और संदेहियों से पूछताछ की जा रही है, चोरों के संबंध में सुराग जुटाए जा रहे हैं, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।

बदलते मौसम पर सतर्क रहें समिति, तेजी से कराएं गेहूं का परिवहन

कलेक्टर ने समय-सीमा की बैठक में दिए निर्देश

नवभारत, कटनी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर आशीष तिवारी ने विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। बैठक में राजस्व, कृषि, स्वरोजगार, नागरिक सेवाओं आदि बिंदुओ पर विशेष रूप से चर्चा की गई। कलेक्टर ने संबल योजना के तहत लंबित आवेदनों के जल्द निराकरण के लिए जनपद पंचायतों के सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देशित किया। साथ ही, उन्होंने जनपद पंचायतों के सीईओ और बीएमओ को आपस में समन्वय कर जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन से जुड़े प्रमाण पत्र समय पर जारी करने के निर्देश दिए। ताकि गर्भवती माताओं के पंजीयन, अन्य शासकीय योजनाओं में पात्र हितग्राही को समय पर लाभ मिल सके। बैठक के दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सीमांकन के दौरान आवेदनकर्ता की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं पाया जाता, लेकिन बगल के भू-स्वामी की भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है, तो आवेदन का इंतजार किए बिना ही अलग से प्रकरण दर्ज किया जाए। कलेक्टर ने बाणसागर परियोजना के अंतर्गत विस्थापितों को भू-अर्जन की लंबित राशि का भुगतान जल्द करने के निर्देश अपर कलेक्टर को दिए गए। कलेक्टर ने उपार्जित गेहूं के परिवहन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बदलते मौसम को देखते हुए समितियों को सतर्क रहने की हिदायत दी, ताकि उपार्जित अनाज को नुकसान नहीं हो।

इसके साथ ही उन्होने किसानों द्वारा उपार्जित गेहूं का जल्द भुगतान दिलाने भी अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में पीएम किसान योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी, फार्मर रजिस्ट्री और फार्मर बकेटिंग की प्रगति की समीक्षा की गई।

सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी, मानकों का नहीं हो रहा पालन

रीठी जनपद के हरद्वार ग्राम पंचायत में बनाई जा रही है सड़क

नवभारत, रीठी। जनपद पंचायत रीठी अंतर्गत ग्राम पंचायत हरद्वारा में सीसी सड़क निर्माण कार्य को लेकर इन दिनों भ्रष्टाचार की चर्चाएं जोरों पर हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी कर शासन की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत हरद्वार में लगभग 9 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। आरोप है कि निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत राशि कई माह पहले ही निकाल ली गई थी, लेकिन सड़क निर्माण का कार्य हाल ही में लगभग पांच-छह दिन पहले शुरू किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि राशि निकाले जाने और कार्य प्रारंभ होने के बीच लंबे अंतराल को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक, जिन्हें वित्तीय प्रभार भी सौंपा गया है, उनके कार्यकाल में निर्माण कार्यों में अनियमितताएं बढ़ी हैं। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सीसी सड़क निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। सड़क की बेस परत में 40 एमएम गिट्टी का उपयोग किया जाना चाहिए, वहां बड़े-बड़े बोल्डर और पहाड़ी पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़क की मजबूती और टिकाऊपन पर प्रश्नचिह्न लग गया है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 150 मीटर सड़क का निर्माण हो जाने के बावजूद संबंधित उपयंत्री द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण नहीं किया गया। जबकि निर्माण कार्य तकनीकी अधिकारियों की देखरेख और उपस्थिति में कराया जाना चाहिए।

अवैध कॉलोनाइजरों पर दर्ज कराएं एफआईआर

नगर निगम आयुक्त ने सरकारी कार्यों की समीक्षा की

नवभारत, कटनी। नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार ने सोमवार को आयोजित समय सीमा बैठक में स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े कार्यों और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि नागरिकों की समस्याओं का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में करते हुए योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में जनसुनवाई, संबल योजना, पीएम स्वनिधि, ई-ऑफिस, ई-केवाईसी, आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली, न्यायालयीन प्रकरणों एवं विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। निगमायुक्त ने कहा कि नागरिकों की शिकायतों के निराकरण की गुणवत्ता एवं समयबद्धता ही प्रशासनिक कार्यप्रणाली की वास्तविक कसौटी है। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। आगामी वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए नगर के बड़े और छोटे नालों की सफाई कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। निगमायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि जलभराव की संभावित समस्या वाले क्षेत्रों में शेष सफाई कार्य प्राथमिकता के साथ पूरा किए जाएं, जिससे नागरिकों को वर्षा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और नाला सफाई के बाद उन्हे प्राथमिकता से ढकनें की नगर निगम जिम्मेदारी है। आईएचएसडीपी योजना अंतर्गत निर्मित आवासों के पात्रता परीक्षण हेतु किए जा रहे सर्वे कार्य की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने शेष सर्वे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की आवासीय योजनाओं का लाभ वास्तविक और पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। निगमायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आरआरसी के प्रकरणों का निराकरण करने, निर्मित आवासों के आवंटन के लिए हितग्राहियों से पैसे जमा कराकर नियमानुसार आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए। नगर की सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को निर्धारित ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र से संचालित किए जाने के लिए नगर सीमा के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में संचालित ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की अद्यतन सूची तैयार करने के निर्देश निगमायुक्त ने दिए। साथ ही ऐसे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी जिन्होंने पूर्व में जारी नोटिसों का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, जिनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई प्रस्तावित करने के निर्देश भी राजस्व अधिकारी को दिए गए। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल स्त्रोतों की सफाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोक पिट निर्माण, बोरवेल रिचार्ज संरचनाओं और पौधारोपण की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने सभी कार्यों की समयबद्ध प्रगति, पोर्टल पर नियमित प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा कर किसी भी आकस्मिक स्थिति में नागरिकों को टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और फायर सेफ्टी मानकों की समीक्षा भी की गई। निगमायुक्त ने अवैध निर्माणों को रोकने, प्रति सप्ताह एफआईआर दर्ज करने, फायर अप्रूवल, फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र नहीं लेने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निगमायुक्त ने बिना अनुमति, अनुमति के विपरीत निर्माण कार्यो की सूची तैयार करने के लिए कहा है।

फल ठेला चालकों से चार प्रतिशत अतिरिक्त कमीशन लेने का आरोप

कार्रवाई की मांग को लेकर फल व्यापारी संघ ने सौंपा ज्ञापन

नवभारत, कटनी। फुटकर फल व्यापारी थोक आढ़तियों की मनमानी और नगर निगम की कार्रवाई से परेशान हैं। सोमवार को फुटकर फल व्यापारी संघ के जिला अध्यक्ष रामराज गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर आशीष तिवारी को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने ज्ञापन में थोक फल आढ़तियों पर अवैध कमीशन वसूलने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा कृषि उपज मंडियों में कमीशन प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध है, इसके बावजूद आढ़ती तय दामों पर फल बेचने के बाद भी ठेला चालकों से 4 प्रतिशत अतिरिक्त कमीशन ले रहे हैं। संघ ने बताया कि 28 मई 2026 को केला व्यापारियों की बैठक में 11 जून 2026 से 10 रुपए अतिरिक्त कमीशन लेने का फरमान जारी किया गया है, जिसके बोर्ड भी दुकानों पर लगाए गए हैं। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि यह मनमानी कृषि उपज मंडी के सचिव की मिलीभगत से चल रही है। संघ ने मांग की है कि थोक आढ़तियों के बैंक खातों और बही-खातों की जांच कराई जाए। साथ ही, कमीशन प्रथा को पूरी तरह बंद कर फलों की बिक्री केवल नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से की जाए। ज्ञापन सौंपने के बाद फुटकर फल व्यापारी संघ के जिला अध्यक्ष रामराज गुप्ता ने बताया कि नगर निगम का अतिक्रमण अमला आए दिन गरीब ठेला वालों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। कलेक्टर ने समस्याओं को सुनने के बाद मंडी प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों से बात कर उचित वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

स्वरोजगार और आर्थिक कल्याण योजना का लें लाभ

नवभारत, कटनी। अनुसूचित जाति वर्ग के युवक, युवतियों के उत्थान के लिए चलाई जा रही संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक युवा योजना का लाभ लेने के लिए एमपी ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है। आवेदन के बाद हॉर्डकॉपी कलेक्टर कार्यालय स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित में जमा करना होगा। इस योजना के अंतर्गत स्वयं का उद्योग, व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाता है।

कार्यक्रम | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरा होने पर 5 से 21 जून तक आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम

केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा

नवभारत, कटनी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए जिला कार्यशाला का आयोजन भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष दीपक टण्डन, जिला संगठन प्रभारी सुजीत जैन के आतिथ्य में किया गया। कार्यशाला में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान एक पेड़ माँ के नाम अभियान, पौधारोपण अभियान, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, प्रगति पथ यात्रा, विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, विशेष जनसंपर्क अभियान, मीडिया संवाद और योग दिवस कार्यक्रमों की सफलता को लेकर जिला टोली, मंडल टोली, जिला पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों, प्रभारियों के साथ रणनीति बनाई गई। बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए टोलियों का गठन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने टोली के संयोजक, सहसंयोजक और सदस्यों की घोषणा की। कार्यशाला में मंचासीन जिला संगठन प्रभारी सुजीत जैन, महापौर श्रीमती प्रीति सूरी, संयोजक रम्मू साहू, श्रीमती सीमा जैन, प्रशांत राय, राजेश पटेल और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला का संचालन जिला महामंत्री मनीष देव मिश्रा जबकि आभार प्रदर्शन प्रशांत राय ने किया।

बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसके लिए संगठन स्तर पर तैयारियां की गई हैं। कार्यकर्ताओं को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए दायित्व सौंपे गए हैं। जिला संगठन प्रभारी सुजीत जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों का कार्यकाल देश के इतिहास में सुशासन, विकास और गरीब कल्याण का स्वर्णिम अध्याय है। यह देश मे परिवर्तन की बुनियाद है। इस अभियान में अधिक से अधिक जन भागीदारी रहे यह हम सभी को सुनिश्चित करना है। उन्होने कहा कि कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है।

महिलाओं, गरीबों, पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कार्य किए हैं। इस अभियान में अपना मूल उदेश्य जन सेवा रखते हुए प्रधानमंत्री जनकल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने की है।

किसानों को 368 करोड़ रूपए का भुगतान

नवभारत, कटनी। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में समर्थन मूल्य पर हुए गेहूं उपार्जन के लिए किसानों को अब तक उपार्जित गेहूं की तुलना में 368.26 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। कलेक्टर आशीष तिवारी ने अधिकारियों को सभी किसानों का शेष भुगतान जल्द करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होने उपार्जित गेहूं के परिवहन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए है। बदलते मौसम को देखते हुए उन्होंने समितियों को सतर्क रहने की हिदायत दी है, ताकि उपार्जित अनाज को नुकसान नहीं हो। जिले में रिकॉर्ड 1 लाख 98 हजार 501 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। जिले के गेहूं खरीदी में इतिहास बनाया गया है।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं महेन्द्र सिंह लोधी पिता मनबोध सिंह लोधी निवासी S/o मनबोध सिंह लोधी 395/1 ग्राम सिहुँडी तहसील बहोरीबंद जिला कटनी म.प्र. पिन 483331 का निवासी हूँ यह है कि मेरा नाम महेन्द्र सिंह था जिसे मैने बदलकर महेन्द्र सिंह लोधी कर लिया है। अत: मुझे महेन्द्र सिंह लोधी के नाम से जाना व लिखा जाए।

पूर्वनाम - महेन्द्र सिंह,
पिता - मनबोध सिंहलोधी
परिवर्तित नाम - महेन्द्र सिंह लोधी
पिता - मनबोध सिंह लोधी